

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8920/2022 Badagaon Stone Quarry Prop. Shri Trilok Grover, Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.85 ha. (75544 Cum per annum) (Khasra No. 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/6, 210/7, 219/1, 219/2, 219/3, 218), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 206, 207, 208, 209/1, 209/2, 210/6, 210/7, 219/1, 219/2, 219/3, 218), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 3.85 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 548वीं दिनांक 10/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 09/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोक ग्रोवर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 160 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 40 मीटर का सेडबेक प्रस्तावित किया गया है।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 458 दिनांक 30/01/19 अनुसार स्वीकृति उत्खनिपट्टा क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में नजदीकी वन कक्ष क्रमांक 477 की दूरी लगभग 210 मीटर है। उक्त क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने के कारण निराकरण हेतु संभाग स्तर समिति के समक्ष प्रेषित किया है। कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की संभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03/02/20 में उक्त क्षेत्र पर वन सीमा की ओर फेंसिंग की शर्त पर खनन की अनुमति प्रदाय की गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खदान में 11 खसरों में आ रही है एवं इन सभी 11 खसरों का सहमति-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का अभिमत है, कि खदान में भू-प्रवेश के पूर्व जिलाध्यक्ष के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि भू-स्वामी का हित किस प्रकार सुनिश्चित होगा एवं उत्खनिपट्टा क्षेत्र के उत्तर-पूर्व में नजदीकी वन कक्ष क्रमांक 477 की दूरी लगभग 210 मीटर है। अतः ई.एम.पी. योजना में चैनलिंग फेंसिंग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

2. Case No 9847/2023 Shri Vinod Lahoti R/o Lahoti Bhawan, Subhash road, Near Post Office, Ward No. 05, Raghogarh, District Guna (MP)- 473226, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.060 ha. (8,000 Cum per annum) (Khasra No. 750) Village-Morukhedi, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [416901].

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 750) Village-Morukhedi, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) 1.060 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण में समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद लाहोटी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मे०. एम.एम. सी. सी. एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 582 दिनांक 27/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 02.96 हे. है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है। खदान क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। खदान की उत्तर दिशा से 100 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है, उत्तर-पश्चिम दिशा में 328 मीटर पर आबादी है, दक्षिण-पश्चिम दिशा में 265 मीटर की दूरी पर आईसोलेटेड बिल्डिंग है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान मेंसर्स तुलसी स्टोन के नाम से थी जिसकी ई.सी. डिया से पूर्व में 2018 को जारी हुई थी (DEIAA EC Letter no. 246 date 14/08/2018) वर्तमान में लीज श्री विनोद लाहोटी के नाम से अंतरण हो चुकी है।

अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में निम्न वांछित जानकारी प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाये :-

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

- डिया से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में वांछित निर्धारित प्रपत्र फार्म-1 में जानकारी
- डिया से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन।
- अनुमोदित खनन योजना का क्लोजर प्लान।
- पूर्व प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत सामाजिक उत्थान के लिये कार्यों की प्रमाणिक जानकारी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद लाहोटी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मे0. एम.एम. सी.सी. एम., भोपाल उपस्थित हुए।

प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि डिया से प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य परियोजना प्रस्तावक ने कार्यालय ग्राम पंचायत मोरुखेडी, जिला देवास का पत्र दिनांक 23/3/23 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि ग्राम पंचायत मोरुखेडी में सर्वजनिक स्थानों पर लगभग 240 पौधारोपण किया गया एवं समय-समय पर सर्वजनिक, स्कूल एवं धार्मिक स्थानों पर मुरुम, गिट्टी एवं मिट्टी देने का कार्य निशुल्क प्रदाय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 8,000 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रु. 05.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.40 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम मोरुखेडी के शासकीय प्राथमिक स्कूल छात्रों के डिजिटल अध्ययन हेतु प्रोजेक्टर 02	60000
ग्राम मोरुखेडी के शासकीय प्राथमिक स्कूल के छात्रों को स्कूली जूते/ मोड़े बितरण छात्रों की कुल) 246 संख्या	70000
योग	1,30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, खमेर, बांस, चिरोल, जंगल जलेबी, काला सिरिस,	400

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

		सफेद सिरिस	
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कला सिरिस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं कुसुम अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ-	200
3	मोरुखेड़ी स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक अन्य स्थानीय प्रजातीय । अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्रीगार्ड के साथ-	100
4	मोरुखेड़ी के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	500
कुल			1200

3. Case No 9791/2023 Smt. Sadhna Sharma W/o Shri Sanjay Sharma, Owner, M/s Om Shri Stone Crusher, R/o Hall-117, Garden Home Face-3, Alkapuri, District- Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Gangapur Stone Quarry in an area of 1.220 ha. (90000 Cum per annum) (Khasra No. 11/1/1 & 11/2/1) Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 11/1/1 & 11/2/1) Village-Gangapur, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) 1.220 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती साधना शर्मा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 316 दिनांक 10/02/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसके उत्तर पूर्वी दिशा में 130 मी. पर नहर, 110 मीटर पर आवास/आबादी एवं 120 मी. पर कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 316 दिनांक 10/02/23 के अनुसार प्रस्तावित खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल की जायेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उत्तर-पूर्वी दिशा में 110 मीटर पर आवास/आबादी के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है किंतु आवंटित खनन क्षेत्र के पास आवास / आबादी होने के कारण खनन कार्य रॉक ब्रेकर से किया जायेगा, जिसका शपथ-पत्र वे प्रस्तुत कर देंगे।

इसी प्रकार प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें मार्च, 20 से कार्य किया जाना गूगल इमेज अनुसार परिलक्षित हो रहा है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको इसी स्थिति में नवम्बर, 2022 में आवंटित हुई है तथा पुराने पिट के विवरण (पिट साईज 3550 X 02 मीटर) अनुमोदित खनन योजना में तथा सरफेस मैप पर दिखाया गया है। चूंकि खदान निजी भूमि पर आवंटित है, अतः यह सत्यापित किया जाना आवश्यक है कि आवेदक ने यह खदान कब कय की, यदि आवेदक द्वारा कय किये जाने के पश्चात् पिट निर्मित हुआ है तो प्रकरण वॉयलेशन का होगा । अतः परियोजना प्रस्तावक यह प्रमाणिक जानाकारी (भूमि की रजिस्ट्री) प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा यह निजी भूमि कब कय की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती साधना शर्मा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 90,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.29 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम गंगापुर के आंगनवाड़ी में 30फिट लंबाई एवं 30 फिट चौड़ाई और 4 फिट उंची कि बाउन्ड्री-वाल का निर्माण ।	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	500

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ट्रीगार्ड के साथ-	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
कुल			1200

4. Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 29/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.105 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है, पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर मंदिर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

प्रस्तावक ने बताया कि खुदी होने के कारण टॉर वॉयलेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार खनन कार्य वर्ष 2014 से 2020 तक बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन कार्य किया गया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर वॉयलेशन (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

दिनांक 09/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022 के माध्यम से स्थल निरीक्षण प्रविदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है पट्टेदार द्वारा यह बताया गया कि उक्त उत्खनन नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुतीकरण के पूर्व स्वीकृत अवधि 25/09/2008 से 24/09/2018 तक के दौरान उक्त सूचना क्षेत्र पर उत्खनन किया गया खसरा न. 499 पर अन्य खदाने संचालित हो रही है ग्राम घटहरी, तहसील – गौरीहार, जिला छतरपुर के खसरा न. 499 पर खनन कार्य किया जा रहा है । प्रस्तुत विवरण (पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022) में मेसर्स आकाश ग्रेनाइट का भी नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि खनन कार्य सतत जारी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है । अतः संबंधित खनिज अधिकारी परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाइट के खनन संचालन अवधि (25/09/2008 से 24/09/2018) का पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें । खसरा न. 499 अन्य प्रचलित खदानों में चैनलिंग फेसिंग आदि का कार्य दृष्टिगत नहीं हो रहा है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी मेसर्स आकाश ग्रेनाइट का जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करें ।

5. प्रकरण क्रमांक 8978/2022 – श्री हेमंत कुमार, ग्राम – गहोरा, तहसील – ईशगढ़, जिला – अशोकनगर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन 27,075 मी.³, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईसागढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 387, रकबा 2.689 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र में 10 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है तथा उनके एवज में 100 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । आवंटित क्षेत्र का वह भाग जहाँ अधिक संख्या में पेड़ लगे हैं, उसे नॉन माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है और वहाँ खनन प्रस्तावित नहीं है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय, सिद्ध बाबा मंदिर की वाऊंड्रीवाल, वृक्षारोपण एवं सड़क का रखरखाव इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को-आर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिण दिशा में 133 मीटर पर प्राकृतिक नाला एवं दक्षिण-पूर्व में 145 मीटर पर जल संरचना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्लूआरडी/जनपद पंचायत में उक्त विषय विशेषज्ञ/सीजीडब्लूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट तथा टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा डा. एस.सी. परांजपे, रि.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

वैज्ञानिक 'डी' हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, भोपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है एवं सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 27,075 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.98 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
4 कंप्यूटर	80,000
1 कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर छात्रों के लिए प्रदान करते हैं	20,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3230 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	हरित पट्टी (3 पंक्ति वृक्षारोपण 7.5 मीटर सुरक्षा बाधा क्षेत्र में किया जाएगा) (क्षेत्र- 0.429 हेक्टेयर)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, काला या सफेद सिरिस, सीस्सु आदि ।	520
2.	अप्रोच रोड के बाहर लीज (1600 मीटर) के साथ ट्री गार्ड (4 फीट ऊंचाई के पौधे)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, कुसुम, चिरोल आदि ।	1600
3.	ग्रामीणों को पौधों का वितरण	आम, पीपल, कचनार, अमरुद, नींबू, कथल, इमली आदि ।	1110
नीम एवं सफेद अरंडी के बीजों की बोआई अनुपजाऊ क्षेत्र से लगभग 500-600 मीटर दक्षिण की ओर कंटूर खाइयों में की जायेगी ।			
कुल			3230

6. प्रकरण क्रमांक 8995/2022 - श्री हितेंद्र प्रताप सिंह, लोधी सुभाष नगर हजीरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टेन क्वेरी, खसरा नं. 388/1, रकबा 03.344 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टेन-27,740 मी.³, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईसागढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 388/1, रकबा 03.344 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईसागढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 554वीं दिनांक 23/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हितेंद्र प्रताप सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके उत्तर-पूर्व क्षेत्र से एच.टी. लाईन निकल रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एच.टी. लाईन के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में लाईन के दोनों ओर 50-50 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है, जिसमें कम ऊँचाई के पौधों का वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र में से एक सरफेस रनऑफ ड्रेन भी निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसको गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के माध्यम से चेनलाईज किया जायेगा। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल छिड़काव, रोड का रखरखाव, वृक्षारोपण एवं आंगनवाड़ी केंद्र में सहयोग एवं मेडिकल कैंप इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-42 के सरल क्रमांक-14 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को-आर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 01 जलाशय है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्ल्यूआरडी/ जनपद पंचायत में उक्त विषय विशेषज्ञ/सीजीडब्ल्यूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट, टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एवं इसका भविष्य में कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हितेंद्र प्रताप सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा डा. एस.सी. परांजपे, (Retd.) वैज्ञानिक 'डी' हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, भोपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है एवं सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 27,075 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

क्रमांक	गतिविधियाँ	प्रदेय	दर	कुल लागत (रु.)
1.	प्रोजेक्ट की आवश्यकता पर 5वीं से 8वीं कक्षा के साइंस लैब इक्विपमेंट	.	.	60,000
2.	हेल्थ चेकअप कैंप	1 स्वास्थ्य शिविर	20000 प्रत्येक	20,000
3.	सिद्ध बाबा मंदिर के चारों ओर बाड़ लगाने और वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत को वित्तीय सहायता	.	.	20,000
कुल				1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	हरित पट्टी (3 पंक्ति वृक्षारोपण 7.5 मीटर सुरक्षा बाधा क्षेत्र में किया जाएगा) (क्षेत्र- 0.494 हेक्टेयर)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, काला या सफेद सिरिस, सीस्सु आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	590

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, कुसुम, चिरोल आदि।	1200
3.	ग्रामीणों को पौधों का वितरण	आम, पीपल, कचनार, अमरुद, नींबू, कथल, इमली आदि।	2210
नीम एवं सफेद अरंडी के बीजों की बोआई अनुपजाऊ क्षेत्र से लगभग 500–600 मीटर दक्षिण की ओर कंटूर खाइयों में की जायेगी।			
			कुल 4,000

7. Case No 8796/2021 M/s. P.S.Stone, Shri Vinod Sharma S/o Shri Brajnaranayan Sharma, Baheriya, Tehsil - Isagarh, Dist. Ashoknagar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.689 ha. (18430 Cum per annum) (Khasra No. 378), Village - Lahadpur, Tehsil - Isagarh, Dist. Ashoknagar (MP) RQP Swati Namdeo, Bhopal.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 378), Village - Lahadpur, Tehsil - Isagarh, Dist. Ashoknagar (MP) 1.689 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान खुदी हुई है डी.जी.पी.एस. करा कर लायेगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद शर्मा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट प्रस्तुत किये गये। गुगल इमेज के अनुसार पूर्व दिशा में एक प्राकृतिक नाला खदान क्षेत्र से लगा हुआ है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया एवं इसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-08 पर दर्ज है।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन — 18,430 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 07.11 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

क्रमांक	गतिविधियाँ	प्रदेय	दर	कुल लागत (रु.)
1.	ग्राम लहदपुर में लीज क्षेत्र के समीप मंदिर के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता।	—	—	10,000
2.	लहदपुर के राजकीय मध्य विद्यालय में टेबल चेयर सेट का वितरण किया गया	लकड़ी का डेस्क. 20	2800 प्रत्येक	56,000
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईसागढ़	1. ऑटोमेटिक डिजिटल बीपी मशीन —2 2. थर्मामीटर — 5 3. As मेडिस्टील Asm-1053 वर्कट्रेस स्टील ब्रेकर ट्रॉली के साथ —2 4. वेल्टन विकार व्हीलचेयर—5	1500प्रत्येक 200 प्रत्येक 10,000प्रत्येक 6000 प्रत्येक	3,000 1,000 20,000 30,000
कुल				1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	हरित पट्टी (3 पंक्ति वृक्षारोपण 7.5 मीटर सुरक्षा बाधा क्षेत्र में किया	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, काला या सफेद सिरिस, सीस्सु आदि।	455

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

	जाएगा) (क्षेत्र— 0.378 हेक्टेयर)		
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, कुसुम, चिरोल आदि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	500
3.	नॉन माइनिंग जोन	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, बबूल, पीपल, बरगद आदि।	200
4.	ग्रामीणों को पौधों का वितरण	आम, पीपल, कचनार, अमरुद, नींबू, कथल, इमली आदि।	875
नीम एवं सफेद अरंडी के बीजों की बोआई अनुपजाऊ क्षेत्र से लगभग 500—600 मीटर दक्षिण की ओर कंटूर खाइयों में की जायेगी।			
			कुल 2030

8. Case No 9854/2023 Shri Siddharth Kushwaha, Owner, Village Rusalla Bamora, District Sagar (MP)- 470004, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19,629 Cum Per Year) (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 326 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः जिसका कुल क्षेत्रफल 04.00 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है जिसमें कुछ पेड़ लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 05 पेड़ लगे हैं जिनमें से 01 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक पक्का रोड 119 मीटर की दूरी पर है दक्षिण दिशा में 358 मी० की दूरी पर एक एम.एस.डब्लू का शेड है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाइल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाइल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 24/05/23 को स्वाईल प्रोफाईल का विवरण प्रस्तुत के साथ ही गूगल इमेज पर खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक 119 दिख रही रोड़ परिवहन मार्ग है, जो दिनांक 09/06/23 को समिति के समक्ष रखा गया । समिति परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेंद्र ठाकुर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह परिवहन मार्ग है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत की गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 19,629 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.24 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
मसवासी ग्रांट के प्राथमिक शाला के बॉउंड्री के अंदर स्थानीय प्रजाति के छायादार वृक्ष लगवाए जायेंगे और साथ में एक फिसल पट्टी और एक झूले भी लगवाया जाएगा	30,000
1 किलो वाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टालेशन के साथ	90,000
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम , महुआ , करंज, कदम , सीताफल, चिरोल, जंगल जलेबी , काला एवं सफेद सिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (पूर्ण सुरक्षा सहित)	300
	ग्रामवासियों में	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता	1500

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

	वितरण हेतु	निम्बू आम कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (सभी पेड़ 1.5 मीटर ऊंचाई के लगाए जायेंगे) हर 4 पेड़ में से एक पेड़ शीताफल का होगा	
			कुल 2400

9. Case No 9853/2023 Shri Raghavendra Thakur, Owner, Ward No. 114, Shahpur Nagar Parisad District Sagar (MP)- 470001, Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone 7858 Cum Per Year & M-Sand 22004 Cum Per Year) (Khasra No. 37/1) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

This is case of Stone and M.Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 37/1 Part) Village-Maswasi Grant, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण में समिति की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेंद्र ठाकुर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 327 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः जिसका कुल क्षेत्रफल 03.0 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 07 पेड़ लगे हैं जिनमें से 07 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। खदान के पूर्व दिशा में 318 मी. की दूरी पर पक्का रोड है एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 184 मी. की दूरी पर कच्चा रोड है, दक्षिण दिशा में 370 मी० की दूरी पर एक एम.एस.डब्लू का शेड है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाइल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाइल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 24/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेंद्र ठाकुर और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाईल प्रोफाईल प्रस्तुत की गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 7858 मी³ प्रति वर्ष एवं एम-सैंड – 22,004 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.66 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.29 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
मसवासी ग्रांट ग्राम के प्राथमिक शाला हेतु बच्चों के लिए 38 कुर्सी टेबल के सेट दिए जायेंगे ।	1,14,000
1 कंप्यूटर एवं ब्लैक – वाइट प्रिंटर टेबल चेयर सेट के साथ दिया जाएगा ।	36,000
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम , महुआ ,करंज, कदम , सीताफल, चिरोल, जंगल जलेबी , काला एवं सफेद सिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (पूर्ण सुरक्षा सहित)	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू आम कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (सभी पेड़ 1.5 मीटर ऊँचाई के लगाए जायेंगे) हर 4 पेड़ में से एक पेड़ सीताफल का होगा	1500
		कुल	2400

10. प्रकरण क्रमांक 8994/2022 - श्री कान्हा गुप्ता, सेवा नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 386, रकबा 02.689 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-25,878 मी.³, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 386, रकबा 2.689 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुरा, तहसील ईशगढ़ जिला-अशोकनगर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 554वीं दिनांक 23/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कान्हा गुप्ता, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके संरक्षण हेतु 50 मीटर का सेट बैक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, सड़क की मरम्मत, इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 57 के सरल क्रमांक 13 पर दर्ज है चूंकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के अक्षांश-देशांश दर्ज नहीं है अतः अनुमोदित खनन योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 120 मीटर पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान एवं इसके आसपास की अन्य खदानें सरपंच द्वारा इस मंशा से स्वीकृत की गई है कि इनके समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो जिससे आसपास के किसानों 02 फसलों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त संदर्भ में तकनीकी रूप से सक्षम हाइड्रोजियोलॉजिस्ट (शासकीय विभाग जैसे : डब्ल्यूआरडी/जनपद पंचायत/सीजीडब्ल्यूओ से अधिकृत) की रिपोर्ट (क्षेत्र का रिचार्ज रेट, टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एवं इसका भविष्य में कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन इत्यादि) प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

श्री कान्हा गुप्ता ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 09/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हेमंत कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा डा. एस.सी. परांजपे, रि. वैज्ञानिक 'डी' हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड, भोपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि समीप स्थित जलाशय के जल संग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है एवं सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,878 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.07.80 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

	Activities	Rate	Total cost (Rs.)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईसागढ़ (Lahadpur)	7 - वेल्टन हेल्थकेयर अस्पताल सेमी फाउलर बिस्तर	10,000/- Each	70,000/-
	Nebulizer- 10	1500 /-Each	15,000
	Oxygen Gas cylinder -3	5000 /-Each	15,000
	2 AS मेडिस्टील ASM-1053 स्टेनलेस स्टील स्ट्रेचर ट्रॉली के साथ	10,000 /-Each	20,000/-
योग			1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3230 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Green belt (3 row plantation will be done in 7.5 m Safety barrier zone) (area- 0.429 ha) in 1st year	Neem, Pipal, Karanj, Chirol, jungle jalebi, Kala or Safed Siris, Sisso etc.	500

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

2	Along approach road outside lease (1.5 m) along with tree guard (plants of height 4ft)	Neem, Pipal, Kachnar, Karanj, Kadam, Kusum, Chirol etc. with tree guard	1200
3	No mining zone	Neem, Pipal, Kachnar, Karanj, Kadam, Chirol etc.	400
4	Distribution of plants to the villagers	Mango, papal, Kachnar, Guava, nimbu, kathal, imli, etc.	1130
Neem and white castor seeds will be sown in contour trenches on the south side of about 500-600 meters from the uncultivated area.			
कुल			3230

11. प्रकरण क्रमांक 8962/2022 – श्री रवि यादव, ग्राम हापाखेड़ी तहसील आरोन जिला गुना (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 374 रकबा 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-24,696 मी.³, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 374 रकबा 3.00 हेक्टेयर, ग्राम लहदपुर तहसील ईशगढ़ जिला अशोकनगर म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16/02/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रवि यादव, (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है के उत्तर-पश्चिम भाग में खनन कार्य किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक ने बिना पर्यावरणीय सम्मति के खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 550वीं दिनांक 16/02/2022 में जब टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी तब उपलब्ध गूगल इमेज अनुसार अक्षांश-देशांश के आधार पर दर्शाये गये स्थल पर कोई खनन गतिविधि नहीं पाई गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको आवंटित क्षेत्र में उनके द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है संभवतः माईन प्लान में गलत अक्षांश-देशांश के कारण मेरे को आवंटित क्षेत्र पास में कार्यरत

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 जून 2023

एक अन्य खदान के ऊपर दर्शित हो रहा है जहां पर वर्तमान में खनन कार्य किया जा रहा है । अतः मुझे एक अवसर दिया जाये ताकि मैं डी.जी.पी.एस. से सही अक्षांस-देशांस निकाल कर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ । समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मानते हुए आवंटित खनन क्षेत्र के अक्षांस-देशांस डी.जी.पी.एस. से प्राप्त किये जाये तथा परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. से प्राप्त अक्षांस-देशांस को संबंधित खनन अधिकारी से प्रमाणीकृत करवाकर 15 दिवस में प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री श्री रवि यादव ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हैं जिनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है । परीक्षण के दौरान पाया कि खदान से लगा हुआ एक खदान है तथा जो खदान से निकल कर तालाब से मिल रहा है, जिससे तालाब में पानी की पूर्ति होती है । उत्खनन किये जाने से जल भराव क्षेत्र विस्तृत होगा तथा यह भी संभावना है कि अतिशेष जल जो तालाब में एकत्रित होकर आगे बहता था अब वह तालाब में एकत्रित हो सकेगा, जिससे भू-जल एवं सतही जल में वृद्धि होगी, जिससे आसपास के कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायी होगा । परियोजना प्रस्तावक ने इसके लिए माइन फेस का उत्खनन दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर दर्शाया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, वृक्षारोपण, जल छिड़काव, सड़क का रखरखाव इत्यादि सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट को शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 24,696 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 17.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 08.93 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. No	Activities	Deliverable	Rate	Total cost (Rs.)
1.	Financial help in Anganwadi of village Lahadpur	--	--	10,000
2.	Table Chair Set Distributed in Government Middle School In Lahadpur.	Wooden School Desk.- 20	Rs. @ Rs. 2800 each	56,000

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईसागढ़ (Lahadpur)	Automatic Digital BP Machine -2	1500each	3,000
		Thermometer – 5	200 each	1,000
		AS मेडिस्टील ASM-1053 स्टेनलेस स्टील स्ट्रेचर ट्रॉली के साथ	10,000 each	10,000
		5 - वेल्टन हेल्थकेयर अस्पताल सेमी फाउलर बिस्तर	10,000 each	50,000
Total				1,30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Green belt (3 row plantation will be done in 7.5 m Safety barrier zone) (area- 0.48 ha)	Neem, Pipal, Karanj, Chirol, jungle jalebi, Kala or Safed Siris, Sisso etc.	530
2	Along approach road outside lease (1.8 m) along with tree guard (plants of height 4ft)	Neem, Pipal, Kachnar, Karanj, Kadam, Kusum, Chirol etc.	1450
3	Distribution of plants to the villagers	Mango, papal, Kachnar, Guava, nimbu, kathal, imli, etc.	1620
4	Green belt (3 row plantation will be done in 7.5 m Safety barrier zone) (area- 0.48 ha)	Neem, Pipal, Karanj, Chirol, jungle jalebi, Kala or Safed Siros, Sisso etc.	530
Neem and white castor seeds will be sown in contour trenches on the south side of about 500-600 meters from the uncultivated area.			
कुल			3600

12. Case No 9851/2023 Shri Shivam Paroha, Owner, Near Mahakaushal School, Rafi Ahmad Kidwai Ward, Murwara, District Katni (MP)- 483501, Prior Environment Clearance for Fire Clay Quarry in an area of 1.620 ha. (12,983 TPA) (Khasra No. 05, 06) Village-Bhaganwara, Tehsil-Bahoriband, District-Katni (MP) –TOR.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

This is case of Fire Clay Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05, 06) Village-Bhaganwara, Tehsil-Sleemanabad, District-Katni (MP) 1.620 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण का समिति की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम परोहा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1853 दिनांक 08/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 04.99 हे० है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में विभक्त है। खदान का पश्चिमी भाग खुदा हुआ है एवं उसमें जलभराव है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में ये खदान (05-06) मेसर्स ए.सी.सी. द्वारा संचालित थी परन्तु exhaust होने एवं अवधि समाप्त होने के कारण बंद है। समिति ने गूगल इमेज में पाया कि पूर्व दिशा में 250 मीटर के अंदर वन क्षेत्र परिलक्षित हो रहा है जबकि एकल प्रमाण-पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र 250 मीटर की परिधि पर कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग से जानकारी प्रस्तुत करे कि उक्त क्षेत्र का लैंड यूज स्टेट्स में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज तो नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/05/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम परोहा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फायरे क्ले – 12,983 टीपीए।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.98 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम भगनवारा शासकीय प्राथमिक शाला में एक हेंडपम्प की स्थापना कराई जायेगी।	40,000 / -

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, अमला, नींबू, अमरुद, जामुन, पपीता एवं अन्य फलदार वृक्ष। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	1000
2	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदंब, अमला, आम, नीम, इत्यादि।	200
3	भगनवारा के ग्राम पंचायत में वितरण हेतु	नीम, पीपल, करंज कचनार, अर्जुन इत्यादि। (पूर्ण सुरक्षा सहित)	700
4	भगनवारा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	हर्रा, बहेड़ा नींबू, कटहल, पपीता इत्यादि।	500
कुल			2400

13. Case No 9150/2022 Smt. Sumitra Grover Owner, Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 483501 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.61 ha. (54405 cum per annum) (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) Env. Consultant M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP,

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 135/1, 135/2, 135/3, 136), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP) 1.61 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 570वीं दिनांक 11/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 09/06/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नीरज कुमार अवस्थी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार पर्यावरण सलाहकार श्री श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 जून 2023

उत्तर-पूर्वी दिशा में 140 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्वी दिशा में 580 मीटर पर आबादी एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में 480 मीटर पर प्राकृतिक नाला है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में 03 पेड़ हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करें :-

- प्रस्तावित खदान के बैरियर जोन में 05 से 06 स्थानों में स्वाइल प्रोफाइल का फोटोग्राफ सहित विवरण तदानुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करें ।
- जन सुनवाई के दौरान आमजनों द्वारा उठाये गये कुछ बिंदुओं को ई.एम.पी./सीईआर में सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः सभी बिंदुओं को ई.एम.पी./सीईआर में शामिल करते हुए बजट सहित प्रस्तुत करें ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m in the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

- damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण । जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

651वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 09 जून 2023

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर